



आधुनिक समाचार

आधुनिक भारत का आधुनिक नजरिया

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक



OCMYB

वर्ष -12 अंक - 120

प्रयागराज, शुक्रवार 20 अगस्त, 2026

पृष्ठ- 8

मूल्य : 3.00 रुपये

ट्रम्प का ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों का फैसला लिया, बोले- जो देश मदद करेंगे उन पर भी एक्शन लेंगे, तेल तस्करी नेटवर्क निशाने पर

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने चेतावनी दी कि ईरान की मदद करने वाले देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई होगी। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने और कैंश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनियों के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की बात कही। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति- 'ये ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई होगी। इसका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसकी सैन्य ताकत पर असर डालना है।' ट्रम्प का दावा- ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके



आर्थिक संकट में है। ट्रम्प ने अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई को 'इकोनॉमिक डी-डे' बताया। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा आर्थिक दबाव बनाने जा रहा है। उन्होंने दूसरे देशों से भी ईरान की मदद बंद करने और अमेरिका के साथ इस अभियान में शामिल होने की अपील की। अमेरिकी प्रतिबंधों का ईरान पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका की नई कार्रवाई का

सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को दुनिया से आर्थिक तौर पर अलग करने की कोशिश करेगा। ईरान का तेल तस्करी नेटवर्क कैसे काम करता है-तेल बेचकर कमाई, पहचान छिपाकर सप्लाई ईरान तेल बेचता है, लेकिन सीधे अपने नाम से कारोबार करने पर अमेरिकी एजेंसियां इसे आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। इसलिए बिचौलियों, दूसरी कंपनियों और अलग-अलग शिपिंग नेटवर्क के जरिए तेल खरीदारों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तेल के बाद पैसे की बारी-तेल बेचने के बाद कमाई को ईरान तक पहुंचाना सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके लिए बैंकिंग चैनल, करेंसी एक्सचेंज, बिचौलियों और कैंश ट्रांसफर जैसे रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका पूरी चेन तोड़ना चाहता है-अमेरिका तेल के साथ उन जहाजों, कंपनियों और वित्तीय नेटवर्क पर भी कार्रवाई करना चाहता है, जो इस कारोबार में मदद करते हैं। इसका मकसद ईरान के लिए तेल बेचना और उससे कमाई मुश्किल करना है।

कमाई का बड़ा हिस्सा तेल बेचने से आता है। अगर दूसरे देश, बैंक और कंपनियां अमेरिकी कार्रवाई के डर से ईरान के साथ कारोबार कम करते हैं, तो ईरान के लिए तेल बेचना और विदेशों से पैसा लेना मुश्किल हो सकता है। तेल की तस्करी और फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई होने से ईरान के लिए छिपकर कारोबार करना और अमेरिकी कार्रवाई से बचना भी मुश्किल होगा। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका अपने

पाक सांसद बोले- यूएई में पाकिस्तानियों से भेदभाव हुआ, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद होटल में कमरा नहीं मिला पर भारतीय-अमेरिकी यात्रियों को रहने दिया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सांसद और नेशनल असंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर यूएई में पाकिस्तानी यात्रियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने



मंगलवार को संसद में कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद होटल में ठहराने के दौरान भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को कमरा दिया गया, जबकि पाकिस्तानी यात्रियों को ठहराने की सुविधा नहीं मिली। कैसर ने दावा किया कि वह खुद इस घटना में दौरान वहां मौजूद थे। उनके मुताबिक, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होटल में ठहराने की व्यवस्था की जा रही थी। कैसर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री से मामले को यूएई अधिकारियों के सामने उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूएई के बीच करीबी रिश्ते हैं और ऐसी घटनाओं को दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं डालना चाहिए। उन्होंने यूएई को पाकिस्तान का 'इस्लामिक भाई देश' बताया हुए कहा कि यूएई के विकास में पाकिस्तानियों का भी योगदान रहा है। कैसर ने यह भी दावा किया कि एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलकर यूएई में इसी तरह के व्यवहार की शिकायत की थी। हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में होटल का नाम, यात्रियों की संख्या या कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया है। यूएई में फ्लाइट कैंसिल होने पर क्या है

की जरूरत के मुताबिक सहायता देनी होती है। अगर यात्रियों को 8 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़े, तो नियमों के तहत होटल, खाना-पीना, कम्युनिकेशन और एयरपोर्ट से होटल तक आने-जाने की सुविधा का प्रावधान है। कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने और अगली संभावित फ्लाइट 8 घंटे से ज्यादा बाद होने पर भी होटल की व्यवस्था की जा सकती है।पासपोर्ट के आधार पर अलग सुविधा का नियम नहीं-जीसी ए के नियमों में होटल और दूसरी यात्री सुविधाओं को फ्लाइट की देरी, कैंसिलेशन और कनेक्शन की स्थिति से जोड़ा गया है। भारतीय, अमेरिकी या पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर अलग-अलग होटल सुविधा देने का कोई सामान्य नियम नहीं है।

इसलिए अगर मौजूदा मामले में पासपोर्ट के आधार पर यात्रियों को अलग सुविधा दी गई, तो यह सामान्य यात्री-सहायता नियमों से अलग मामला होगा।

हालांकि, अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती कि होटल ने वास्तव में पासपोर्ट के आधार पर ही यात्रियों को कमरे दिये थे।

बांग्लादेश बोला- भारत से गंगा जल समझौते में गारंटी मांगेंगे,जरूरत पड़ी तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाएंगे, 1996 का समझौता दिवसेंवर में खत्म होगा
दिल्ली/ढाका। बांग्लादेश गंगा जल संधि में भारत से 'गारंटी कलॉज' शामिल करने की मांग कर रहा है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधुरी एनी ने मंगलवार को ढाका में यह बात कही। शाहिदुद्दीन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठा सकता है। दरअसल, भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगी। यह समझौता जनवरी से मई के बीच बांग्लादेश को गंगा का पानी देने से जुड़ा है। बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि सुखे मौसम में उसकी जरूरत के मुताबिक पानी उपलब्ध नहीं कराती है। इसलिए वह नई संधि में ऐसा प्रावधान चाहता है, जिससे भारत निश्चित मात्रा में पानी की आपूर्ति की गारंटी दे। इसी के तहत बांग्लादेश 'गारंटी कलॉज' में न्यूनतम जल प्रवाह तय करने की मांग कर रहा है। भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि की शर्त-70 हजार क्यूसेक या उससे कम: दोनों को 50-50फीसदी पानी-70 से 75 हजार क्यूसेक: बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक, बाकी भारत को 75 हजार क्यूसेक या ज्यादा: भारत को 40 हजार क्यूसेक, बाकी बांग्लादेश कोयह समझौता 1 जनवरी से 31 मई तक के लिए लागू होता है।आगे की खबर पेज संख्या 07 पर..

बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव,रूलिंग पार्टी, बीएनपी के उम्मीदवार की जीत तय, 11 दलों वाले गठबंधन से मुकाबला

ढाका। बांग्लादेश में 35 साल बाद आज राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। वोटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में



हैं।बीएनपी उम्मीदवार के सामने मुख्य विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (रिटायर्ड) ओली अहमद हैं। बीएनपी के खिलाफ 11 दलों का गठबंधन-350 सीटों वाली संसद में बीएनपी के पास 247 सांसद हैं। वहीं, मुख्य विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी की अगुआई वाले 11 दलों के गठबंधन के पास 81 सांसद हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 349 सांसद वोट डालेंगे। चटगांव-4 सीट फिलहाल खाली है। अदालत के आदेश के बाद इस सीट से निर्वाचित उम्मीदवार की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक वोटिंग-राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वोट राष्ट्रीय संसद के सत्र कक्ष में डाले जाएंगे। मतदान शुरू होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन सांसदों को वोट डालने का तरीका समझाएंगे।

जलवेधन मंगलवार का बताया कि दोनों उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया है। नाम वापस लेने की समय सीमा मंगलवार शाम 4 बजे खत्म हो गई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। आखिरी बार 1991 में चुनाव में मुकाबला हुआ था-बांग्लादेश में अब तक 12 राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। इनमें 8 बार राष्ट्रपति निर्वाचन चुने गए। संविधान लागू होने के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव 1974 में हुआ, जिसमें सांसदों ने वोट देकर मोहम्मद मोहम्मदुल्लाह को चुना। 1975 में संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता से कराने की व्यवस्था हुई। इसके तहत 1978, 1981 और 1986 में लगातार तीन बार जनता ने राष्ट्रपति चुनाव। 1991 में फिर संसदीय व्यवस्था लागू हुई और राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा सांसदों के जरिए होने लगा। 1991 में दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ।

भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, 12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट, दोनों देशों में सीमा विवाद पर होगी बात

नई दिल्ली। भारत में 12-13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में शामिल



होने की पुष्टि है। वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की तैयारियां चल रही हैं। अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो यह करीब 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वे अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, चीन की ओर से जिनपिंग के दौरे की अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, दोनों

देशों की एडवांस टीमों के दौरे और अन्य तैयारियों से उनके भारत आने की संभावना जताई जा रही है। जिनपिंग से बातचीत में सीमा विवाद सबसे अहम मुद्दा-जिनपिंग के भारत दौरे की तैयारियों में एलएसी पर शांति और सीमा विवाद सबसे अहम मुद्दे में हैं। दोनों देश सीमा पर ऐसी व्यवस्था बनाने पर बात कर रहे हैं, जिससे किसी सैन्य घटना या तनाव का असर द्विपक्षीय रिश्तों पर न पड़े। जिनपिंग की संभावित यात्रा से पहले एनएसए अजीत डोभाल सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए बीजिंग जा सकते हैं। वहां उनकी चीन के विदेश मंत्री वंग यी से मुलाकात हो सकती है। बातचीत में सीमा प्रबंधन, तनाव कम करने और स्थायी शांति के उपायों पर फोकस रहेगा। व्यापार और जरूरी सामान की सप्लाई भी एजेंडे में-भारत और चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं, बल्कि व्यापार और आर्थिक रिश्ते भी बातचीत का हिस्सा हैं।

टीचर की पिटाई से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, विशाखापट्टनम का मामला

विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में गुरुवार को टीचर की पिटाई से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। सीसीटीवी में नजर आया कि पिटाई के बाद बच्चा टीचर की गोद में ही गिर पड़ा। परिजनों का आरोप है कि टीचर की पिटाई से बच्चे को दहशत में हार्ट अटैक आ गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि टीचर ने उसके कपड़े उतारने की कोशिश की और धपड़ मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक प्रणय तेजा लिटिल गार्डन्स स्कूल के यूकेजी में पढ़ता था। टीचर की गोद में गिरने के बाद बच्चे को किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी सामने आने में कहा गया है कि घटना का पता तब चला जब क्लास का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया। आरोप है कि यह सब होमवर्क न करके पर बच्चे को शर्मादा करने के लिए किया जा रहा था। बच्चा रोते हुए टीचर को रूकने का इशारा करता दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच करेगी बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री-पुलिस ने बच्चे की मौत की वजह की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि बच्चे को पहले से कोई बीमारी थी या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की जानकारी सामने आएगी। परिवार ने बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला,दो दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई हुई थी

नई दिल्ली। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को बुधवार देर रात बुलडोजर से हटा



दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, ये ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने थे। पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी के शांतिपथ पर है। यहां बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रबंधन के लिए बनाए गए ढांचे भी हटाए गए। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब दो दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे। वीजा सेक्शन के पास के ढांचे भी हटाए-संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी की मदद से हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई की। मौके से ली गई तस्वीरों में टूटी रेलिंग, गेट, लोहे के फ्रेम, छत की चादरें, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। बाहरी हिस्से की सफेद मेटल फेंसिंग

की मेन बिल्डिंग तक नहीं हुआ। मेन गेट, सफेद दीवारें और पाकिस्तानी निशान वाला बड़ा प्रवेश द्वार सुरक्षित रहा। परिसर के कुछ हिस्सों में कांटेदार तार भी लगे दिखाई दिए। तोड़फोड़ के बाद वीजा सेक्शन के सर्विस काउंटर दिखाई दे रहे थे। वहां 'विंडो 1', 'पाकिस्तान पासपोर्ट ऑनली' और 'विंडो-5 / कलेक्शन ऑफ वीजा एप्लीकेंट्स' जैसे बोर्ड लगे थे। काउंटरो के आसपास टूटी फेंसिंग और कंस्ट्रक्शन सामान पड़े थे। कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत वगी टिप्पणी से पाकिस्तान नाराज-दोनों देशों के बीच अमेरिकी राजदूत की कश्मीर पर टिप्पणी का लेकर भी तनाव बढ़ा है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर दौरे के दौरान 19 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को भारत का

महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्षेत्र के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। पाकिस्तान ने सर्जियो के बयान पर ऐतराज जताया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स नताली बेकर को तलब किया और कहा कि सार्वजनिक बयानों में कश्मीर की स्थिति का ध्यान रखा जाए। पाकिस्तानी दूतावास 'एम्बेसी' नहीं, 'हाई कमीशन' क्यों कहलाता है-भारत और पाकिस्तान दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, इसलिए दोनों देशों के राजनयिक मिशन को 'हाई कमीशन' कहा जाता है। यहां नियुक्त सबसे बड़े राजनयिक को हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त कहा जाता है। वहीं, गैर-कॉमनवेल्थ देशों में राजनयिक मिशन को एम्बेसी और उसके प्रमुख को एम्बेसडर यानी राजदूत कहा जाता है।दोनों का काम लगभग एक जैसा होता है। अंतर मुख्य रूप से नाम और राजनयिक परंपरा का है। उदाहरण के लिए, भारत का पाकिस्तान और ब्रिटेन में हाई कमीशन है, जबकि अमेरिका में एम्बेसी है। कॉमनवेल्थ 56 स्वतंत्र और समान देशों का संगठन है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े देशों के बीच सहयोग के लिए हुई थी।

हालांकि, आज इसके सभी सदस्य देश पूरी तरह स्वतंत्र हैं और अपनी सरकार, विदेश नीति और दूसरे फैसले खुद लेते हैं। इसलिए 'हाई कमीशन' शब्द का इस्तेमाल आज किसी देश के ब्रिटेन के अधीन होने को नहीं दर्शाता।

अमेरिका ने 15 दिन में 5200 भारतीय डिपोर्ट किए,इस साल हर तीसरे हफ्ते डिपोर्टेशन फ्लाइट कनाडा में 1500 भारतीय छात्रों को वापस भेज सकते हैं

न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दूसरे साल मिशन डिपोर्टेशन तेज कर दिया है। इस अगस्त के पहले 15 दिन में ही 5200 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इस बार की डिपोर्टेशन लिस्ट में एच-1 बी, ओ-1 और स्टूडेंट वीसा पर अमेरिका गए भारतीय भी शामिल हैं। इन प्रोफेशनल्स की भी अच्छी खासी संख्या है। इस साल हर तीसरे हफ्ते में एक डिपोर्टेशन फ्लाइट रवाना की जाई। वहीं, कनाडा के अलर्टा प्रांतीय सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्कॉ परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) रद्द कर दिया। अब वहां पर पढ़ाई कर रहे लगभग 1500 भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ गया है। इमिग्रेशन एजेंसी (आईएस) के एक अधिकारी के अनुसार अवैध प्रवासियों के खिलाफ इनकी धरपकड़ और डिपोर्टेशन दोनों की संख्या बढ़ी है। इस साल के अंत तक डिपोर्ट किए जाने वाले अवैध प्रवासियों की रिकॉर्ड संख्या होने वाली है। पिछले साल यानी 2025 में डिपोर्ट किए गए तीन हजार से ज्यादा भारतीयों में सभी ऐसे थे,

जो अवैध रूप से अमेरिका में आए थे। आईस ने जून में ही 801 भारतीयों को रिमूवल ऑर्डर

से नई दिल्ली भेजा जा रहा है। इस साल डिपोर्टेशन उड़ानों का इस्तेमाल किया जा रहा है।



(वापसी आदेश) जारी किया। हालांकि, इस रिमूवल ऑर्डर से तुरंत डिपोर्टेशन नहीं होता है। इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकती है या फिर संबंधित व्यक्ति अपनी इच्छा से अमेरिका को छोड़ सकता है। 2025 में डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या 16 साल में सबसे ज्यादा थी। ह्यूमन राइट्स फर्स्ट संगठन के अनुसार भारतीयों को ओमान की एयरवेज से डिपोर्ट कर रहे हैं। टेक्सस के हार्लिंग से 20 घंटे की फ्लाइट

पिछले साल अमेरिका ने सैन्य विमान हरक्यूलिस से डिपोर्ट किया था। ट्रैफिक लाइट पार करने या सोशल मीडिया पोस्ट पर भी कार्रवाई-वैध वीसा पर आए प्रोफेशनल्स को किसी भी उल्लंघन का आरोप लगा डिपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका के किसी शहर में ट्रैफिक लाइट पार करने पर भी छात्रों को डिपोर्ट करने के मामले सामने आए हैं। कुछ छात्रों द्वारा सोशल मीडिया जैसे एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रम्प सरकार की

आलोचना का दोषी मानकर डिपोर्ट कर दिया गया। टेक्सस में एच-1बी वीसा होल्डर की जाँच चली गई, जबकि उसके पास 60 दिन तक अमेरिका में रहकर नहीं जाँच सर्व करने का अधिकार था। इस बीच, एक रेस्तरां में पाट टाइम जाँच करते समय आईस ने रेड डाली। वीसा होल्डर को पकड़ लिया गया। उसे आईस ने वीसा उल्लंघन का दोषी माना और भारत डिपोर्ट कर दिया। 2025 में 3,567 भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट हुए थे-2025 में अमेरिका ने 3,567 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया था। यह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने जून 2026 में दी थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2026 में जून तक 1076 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है।

5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने पहली बार सैन्य विमान से 104 भारतीयों को अमृतसर भेजा था। इस दौरान कई लोगों को हथकड़ी और पैरों में बैडियां लगी थीं। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद देशभर में विवाद हुआ। संसद में भी हंगामा हुआ था।

बांग्लादेशी नेता बोला- हिंदुओं को आसानी से मार सकते हैं,अल-कायदा से जुड़े हारून इजहार का बयान सोशल मीडिया पर वायरल

ढाका। बांग्लादेश में अल-कायदा से जुड़े नेता हारून इजहार का हिंदुओं को लेकर विवादित बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वह कहता नजर आ रहा है कि हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है। यह वीडियो चटग्राम में आयेजित एक कार्यक्रम का है। इसमें इजहार यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके समर्थक ही ऐसा करने के लिए काफी हैं। शैख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों और भेदभाव के कई आरोप लग



रहा है। उसके पिता मुफ्ती इजहारुल इस्लाम भी चटग्राम के एक चर्चित इस्लामी नेता और मदरसा संचालक रहे हैं। हारून

का नाम लंबे समय से कट्टरपंथ और हिंसक गतिविधियों से जुड़े मामलों में सामने आता रहा है। 2013 में चटग्राम के लालखान बाजार स्थित मदरसे में विस्फोट हुआ था। इस घटना में तीन लोगों की मौत हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने विस्फोटक बनाने की सामग्री, तेजाब और बिना फटे ग्रेनेड बरामद किए थे। इस मामले में हारून और उसके पिता समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ था। अल-कायदा से कनेक्शन का क्या मामला है? हारून इजहार को लेकर अल-कायदा और दूसरे जिहादी नेटवर्क से संबंधों के आरोप पुराने हैं। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में उसके

पिता के मदरसे को प्रतिबंधित संगठन हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी बांग्लादेश के नेटवर्क से जोड़कर देखा गया है। उसके पिता के ओसामा बिन लादेन और तालिबान नेता मुल्ला उमर से संपर्क होने का भी दावा किया गया है। रिपोर्ट्स में हारून इजहार को कट्टरपंथी संगठन हेफाजत-ए-इस्लाम का सीनियर नेता बताया हुए उसके अंतरराष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क से कथित संबंधों का जिक्र है। 2021 में भी हिंसा के मामले में नाम आया-मार्च 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान चटग्राम और दूसरे इलाकों में हिंसा हुई थी।

ग्रामीण युवाओं को टीबी उन्मूलन अभियान से जोड़ रहा स्वास्थ्य विभाग

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को टीबी उन्मूलन अभियान से जोड़ने के लिए जिला क्षय रोग केंद्र पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनुपम सिंह एवं जिला युवा अधिकारी वरिंका सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में जिला प्रोग्राम समन्वयक अभय मिश्रा, जिला पब्लिक प्राइवेट मिक्स समन्वयक मनीष श्रीवास्तव एवं जिला टीबी-एचआईवी समन्वयक अतुल कुमार ने माई भारत वॉलंटियर्स को क्षय रोग के लक्षण, जांच, उपचार और बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम (इंटरलपी) के तहत प्रशिक्षण के तीसरे दिन बुधवार को माई भारत वॉलंटियर्स की टीम को जिला क्षय रोग केंद्र (डीटीसी) स्थित

टीबी यूनिट का भ्रमण कराया गया। इस दौरान वॉलंटियर्स को केंद्र के विभिन्न काउंटरों की उपयोगिता, वहां होने वाली जांच तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवीन चंद्र ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को टीबी उन्मूलन अभियान से जोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल शुरू की है। इसके तहत माई भारत वॉलंटियर्स द्वारा रायबरेली और जिला क्षय रोग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायबरेली वेग हरचंदपुर, ऊंचाहार, डलमऊ, शिवगढ़ और अमावां ब्लॉक के चयनित गांवों के युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही लखीमपुर, बाराबंकी, अयोध्या, इटावा, कन्नौज और वाराणसी के चयनित ब्लॉकों में भी यह पहल शुरू की गई है। जिला क्षय रोग

केंद्र पर 17 से 21 अगस्त तक चल रहे प्रशिक्षण में युवाओं को टीबी के लक्षण, जांच, निदान, उपचार और बचाव की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद ये युवा अपने गांवों में लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने के साथ संभावित मरीजों की पहचान कर उन्हें जांच और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में विभाग का सहयोग करेंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनुपम सिंह ने बताया, 'टीबी उन्मूलन अभियान में युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। चयनित पांच गांवों के 50 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें टीबी की पहचान, बचाव और उपचार की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद ये युवा अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के साथ संभावित मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी की समय से पहचान और उपचार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।'

रोजगार मेला राजकीय आईटीआई में AGI GREENPAC LIMITED, HYDERABAD (HINDWARE/SOMANY IMPRESA) के द्वारा साक्षात्कार हेतु सूचना (आधुनिक समाचार नेटवर्क) CSR स्टैंडर्ड 15000/- रुपये रायबरेली। राजकीय औद्योगिक प्रतिमाह देय है तथा रेगुलर होने



प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली में दिनांक 25/08/2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें AGI GREENPAC LIMITED, HYDERABAD (HINDWARE/SOMANY IMPRESA) कंपनी के लिए के लिए 120 पदों पर भर्ती होगी। इस मेले में ITI (समस्त व्यवसाय)/DIPLOMA/B.TECH (Mechanical/Electrical/Electronic) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी उम्र सीमा कंपनी है तो 18 से 32 वर्ष, है और पर वेतन 17500-25000/- रुपये प्रतिमाह देय होगा। साथ में कंपनी के नियमानुसार कैंटीन की सुविधा वरिंका अन्य मुफ्त में देय है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना संक्षिप्त बायोडाटा सभी अंक पत्रों एवं तकनीकी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, (यदि उपलब्ध है तो) लेकर प्रातः 09-00 बजे से 3-00 बजे तक सम्मिलित हो सकते हैं चयन प्रक्रिया लिखित साक्षात्कार के माध्यम से होगा।

आईजी पीएसी पूर्वी जोन श्री धर्मवीर ने किया 42वीं वाहिनी पीएसी नैनी का आकस्मिक निरीक्षण

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। दिनांक

परखने के लिए आईजी महोदय ने कंट्रोल रूम, प्रधानलिपिक

जवानों की बात सुनी और अधिकारियों को निम्नलिखित मुख्य निर्देश दिए। स्थानीय समन्वय: बाह्य जनपदों में ड्यूटी के दौरान स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन से बेहतर तालमेल बनाया जाए। त्वरित भुगतान: जवानों के टीए/डीए (TA/DA) और चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के मामलों का समय से निस्तारण हो। सुविधाएं: वाहिनी और ड्यूटी पर तैनात दलों को रहने व खाने की सभी बुनियादी सुविधाएं उच्च स्तर की मिलनी चाहिए। सम्मेलन का समापन: रात्रिभोज के साथ हुआ। इस अवसर पर



20.08.2026 को पुलिस महानिरीक्षक (IGP), पीएसी पूर्वी जोन, प्रयागराज श्री धर्मवीर (धर) द्वारा सेनानायक श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (IPS) की गरिमामयी उपस्थिति में 42वीं वाहिनी पीएसी नैनी, प्रयागराज का आकस्मिक निरीक्षण व भ्रमण किया गया। वाहिनी आगमन पर मुख्य अतिथि को टूटपॉस्ट भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद महानिरीक्षक महोदय ने क्वार्टर गार्ड पर सशस्त्र सेरेमोनियल गार्ड से सलामी ली। गार्ड के बेहतरीन टर्न-आउट और अनुशासन को देखकर आईजी महोदय ने गार्ड की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इसके उपरांत उन्होंने कोत (शस्त्रागार) और वाहिनी ब्रॉस बैड का निरीक्षण कर

कार्यालय, सहायक सेनानायक कार्यालय, आंकिक कार्यालय, एस0ए0 कार्यालय, जी शाखा



कार्यालय, गोपनीय कार्यालय और मुख्यालय शाखा सहित पूरी

उपसेनानायक श्री उदय प्रताप सिंह, सहायक सेनानायक श्री



आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए महोदय द्वारा 'वामा सारथी उद्यान' में पौधारोपण भी किया गया। कार्यालयों का सघन निरीक्षण-भ्रमण के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को

वाहिनी का विस्तृत निरीक्षण किया। सैनिक सम्मेलन में दिए कल्याणकारी निर्देश-निरीक्षण के बाद एक 'सैनिक सम्मेलन' का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 'पीएसी गान' से हुई। सम्मेलन में आईजी महोदय ने

देव नारायण यादव, सहायक सेनानायक श्री वेद प्रकाश राय, शिविरपाल श्री अरविंद कुमार सिंह, सूबेदार मेजर श्री सुधांशु कुमार सहित वाहिनी के समस्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

नवागत खंड शिक्षा अधिकारी का शिक्षक संघ ने किया भव्य स्वागत

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। दीनशाह गौरा।

शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का

प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन के मंत्री अखिलेश



ब्लॉक संसाधन केंद्र, दीनशाह गौरा में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा गौरा के अध्यक्ष शैलेश पांडे के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा नवागत खंड शिक्षा अधिकारी, दीनशाह गौरा सुधा वर्मा का आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुधा वर्मा ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता परिषदीय बच्चों का शिक्षण मानक स्तरीय, गुणवत्तापूर्ण एवं सुचारु रूप से समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखते हुए विद्यालयों में बेहतर

सहयोग आवश्यक है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा गौरा के अध्यक्ष शैलेश पांडे ने नवागत खंड शिक्षा अधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन शिक्षक हितों के साथ-साथ परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खंड शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन एवं शिक्षकों के सहयोग से दीनशाह गौरा में शैक्षिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से विभागीय कार्यों एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए हरसंभव सकारात्मक सहयोग

कुमार, संरक्षक त्रिलोकी शरण सिंह, जिला उपाध्यक्ष उमेश त्रिवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुनेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, संयुक्त मंत्री श्रीराम श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष श्याम सिंह, दिनेश मिश्रा, मनीष दीक्षित, नितिन सोनी, राहुल द्विवेदी, दीपक शुक्ला, राम अवध मौर्या, रविंद्र सिंह, गुंजन त्रिवेदी, कुवर जी यादव समेत बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिका उपस्थित रही। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान संगठन की ओर से नवागत खंड शिक्षा अधिकारी को शुभकामनाएं एवं सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी गई।

मां-बाप को उम्रकैद, बेटी ने लव मैरिज की थी, घर में गोली मारी, लाश सूटकेस में भरकर मथुरा में फेंका

मथुरा। मथुरा के चर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में मां-बाप को उम्रकैद की सजा हुई है। मथुरा कोर्ट ने 4 साल बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट में आयुषी के पिता नितेश यादव ने अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहा कि बेटी की हत्या मैंने की थी, पत्नी का दोष नहीं है। फिर चुप हो गए। मां सिर झुकाए खड़ी रही। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा- बेटी की हत्या का अपराध अत्यंत क्रूर और वीरस की श्रेणी में आता है। इसलिए दोषियों पर नग्न रुख अपनाने का कोई आधार

नहीं है। अगर दोषी को दंडित नहीं किया तो समाज में गलत संदेश जाएगा। 22 साल की इकलौती बेटी आयुषी की 4 साल पहले पिता नितेश यादव ने दिल्ली स्थित अपने घर में रिवांल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि आयुषी ने राजस्थान के युवक से चुपके से लव मैरिज कर ली थी। हत्या के बाद पिता ने शव को लाल सूटकेस में भरकर 150 किलोमीटर दूर मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस-वे पर फेंक दिया था। इसमें आयुषी की मां ब्रजवाला ने उनका

साथ दिया था। शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मथुरा पुलिस मां ब्रजवाला और आयुषी के भाई आयुष को मथुरा लेकर आई। दोनों ने आयुषी की पहचान की थी। बाद में पुलिस ने मां-बाप को गिरफ्तार किया था। पिता की दिल्ली में दुकान थी। सरकारी वकील मुकेश गोस्वामी ने कहा- पुलिस ने जांच के बाद नितेश यादव और ब्रजवाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने गवाहों के बयान और केस से जुड़े सबूत कोर्ट के सामने रखे।



INDIAN SECURITY AND MANPOWER SERVICE

ADDRESS- Naini, Prayagraj U.P.-211008. PAN No. ABJPA1540R, Reg.No.03-0068604

Regd. Under Additional Director General of Police U.P. vide Reg. No. 2453 +91-7985619757, +91-7007472337

We Are Providing Security & Manpower Services in School/ University/ Institute/ Hospital/ Office Premises

INDIAN SECURITY AND MANPOWER SERVICES:- takes great pleasure in Providing Security arrangement and Office Staff for your Organization premises. We have with us talented and well trained Disciplined persons, each having exposure to industrial/commercial security and intelligence knowledge in their field. Our personnel's are physically fit, courageous disciplined and well trained in their field. They are bold but polite, peace loving but not coward, friendly but shrews while duty, sharp in act but very claim and affable where presence of mind is lost by the common man, ailing but smelling the red hounds, work in the common climate but vigilant and faithfully to the organization. It is on account of the above trait that our services are engaged by reputed organization which consists of Schools, University, Banks, Government, Industrial Concern, Hotels, Hospitals, Educational Institutes, Housing Societies/Bungalows, Semi Government and Government Organization.

INDIAN SECURITY AND MANPOWER SERVICES is registered by:-
Additional Director General of Police, (Law & Order), Deputy Labour Commissioner, Employees Provident Fund Organization, Employees State Insurance Corporation, Goods & Services Tax, MSME Registration..(Govt. of India)

FOR JOB CONTACT:- 9569430885

INDIAN SECURITY AND MANPOWER SERVICES Manpower Category:-
Assignment Manager, Housekeeping Manager, Assignment Supervisor, Housekeeping Supervisor, Accountant, Driver, Computer Operator, Electrician, Data Entry operator, Carpenter, Clerk, Office Boy, M.T.S, Sweeper, Peon, Gardner, Computer Teacher, Agriculture Labour, TGT & PGT Teacher, Quality/Technical Manpower as per your requirement



दिल्ली-एनसीआर में बारिश, प्रयागराज में 5 फीट पानी भरा, 2000 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ा

लखनऊ। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार

से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। पन्ना के कई गांवों में भी पानी भर गया। वहीं, उत्तराखंड

घरों में 3-3 फीट पानी भर गया। 2 हजार से ज्यादा छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया। 7 हजार से



सुबह तेज बारिश हुई। एयरपोर्ट रोड पर द्वाका अंडरपास समेत कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को मुश्किल हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चार दिनों से बारिश हो रही है। पिछले तीन दिन में 205 मिमी पानी गिरा। शहर के कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया। घरों-हॉस्टल में पानी भर गया। बुधवार को करीब 2000 छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए। आज भी 9 जिलों में रेड अलर्ट है। वाराणसी में घाटों के किनारे 100 से ज्यादा मंदिरों में गंगा का पानी घुस गया है। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट में छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सतना में भारी बारिश से चित्रकूट की गुप्तगोदावरी में जलस्तर बढ़ गया। डिंडोरी में नदी-नाले उफान पर हैं और 12

में बारिश से जुड़ी घटनाओं में बुधवार को 4 लोगों की मौत हुई। इनमें 2 साल का बच्चा और दिल्ली की 25 साल की महिला भी शामिल हैं। उधर, हिमाचल प्रदेश में बारिश-लैंडस्लाइड के कारण 88 सड़के बंद हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के इलाकों में 200 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। देहरादून समेत कई इलाकों में टोस, तमसा, आसन और रिस्पना नदियों में पानी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे जाने और जोखिम वाले इलाकों में सेल्फी लेने से बचने की सलाह दी है। हर दिन करीब 8 से 9 हजार श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मौसम बिगड़ने पर जिला प्रशासन करीब 12 घंटे तक यात्रा रोक सकता है। प्रयागराज में 4 दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। दारागंज, कर्ली, सलोरी जैसे इलाकों में

ज्यादा परिवार छतों पर रह रहे हैं। हाईकोर्ट ने डीएम मनीष वर्मा से सख्त लहजे में कहा- 24 से 48 घंटे में शहरी इलाकों से पानी निकल जाना चाहिए। चित्रकूट में मंदाकिनी, अयोध्या में सरयू, गोडा में भी घाघरा खतरे के निशान को पार कर गई। चित्रकूट में पानी सड़कों तक पहुंच गया। सड़कों पर नावें चल रही हैं। सोनभद्र में इस सीजन पहली बार कनहर बांध के 14 फाटक एक साथ खोलने पड़े। लखीमपुर खीरी के प्राइमरी स्कूल में 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया। स्नैक कैचर ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 63 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। प्रयागराज में 12वीं, कौशांबी व चंदौली में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यर्थियों को अधिकारियों द्वारा मिलेगा मेंटरशिप मार्गदर्शन

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जनपद के पीएम श्रम राजकीय इंटर कॉलेज, रायबरेली में निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। शासनदेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपद में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के

मेंटरशिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली एवं उत्साही अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न अधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथियों पर मेंटरशिप प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण का समय दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक निर्धारित है। निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार जिला

युवा अधिकारी (शर्द्धा) वर्तिका 22 अगस्त 2026 एवं 26 दिसंबर 2026 को, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महिमा 26 सितंबर 2026 एवं 23 जनवरी 2027 को, खंड विकास अधिकारी महाराजगंज श्रद्धा सोनकर 24 अक्टूबर 2026 एवं 27 फरवरी 2027 को तथा तहसील-सदर के नायब तहसीलदार हरिश्चंकर सिंह 28 नवंबर 2026 एवं 27 मार्च 2027 को अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

डीएल की परीक्षा में फेल हुए तो प्रशिक्षण के लिए देंगे होंगे 6 हजार रुपये, सोनभद्र समेत पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था के लिए शासनादेश जारी, अब तक दोबारा शुल्क देकर परीक्षा में शामिल होने का था प्रावधान

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में अब वाहन चालकों को परीक्षा के दौरान अधिक सतर्क रहना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल)

की परीक्षा में असफल होने के बाद आवेदक निर्धारित शुल्क जमा कर दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकता था। नई व्यवस्था के तहत यह प्रक्रिया बदल दी गई है। परीक्षा में फेल

पर रोक लगाना और लाइसेंस जारी करने से पहले चालक की वास्तविक दक्षता सुनिश्चित करना है। इससे वाहन चालकों को यातायात नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क पर वाहन



की परीक्षा में फेल होने वाले आवेदकों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब दोबारा परीक्षा देने से पहले निर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदक को करीब छह हजार रुपये का शुल्क के तौर पर जमा करना होगा। जनपद में शासन द्वारा पीपीपी मॉडल पर मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण और परीक्षण केंद्र संचालित है। जिसमें तेज सिंह प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र व सेफ रोड परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। इन केंद्रों पर दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों की प्रशिक्षण के साथ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा की सुविधा है। अब तक

होने वाले आवेदक को पहले प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण लेना होगा और इसके बाद ही दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देने का अवसर मिलेगा। सोनभद्र में भी स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों पर इसका असर पड़ेगा। परिवहन विभाग की ओर से वाहन चालकों को ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के अनुसार वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभाग का मानना है कि प्रशिक्षण को अनिवार्य किए जाने से वाहन चालकों की दक्षता बढ़ेगी और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के बार-बार ड्राइविंग टेस्ट देने की प्रवृत्ति

संचालन के जरूरी मानकों का प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। परिवहन विभाग के एआरटीओ कौशल कुमार सिंह के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस केवल दस्तावेज नहीं बल्कि सड़क पर वाहन चलाने की जिम्मेदारी से जुड़ा प्रमाण है।

इसलिए परीक्षा में सफल होने के लिए आवेदकों को निर्धारित प्रशिक्षण और ड्राइविंग मानकों की जानकारी होना जरूरी है। मोटर ट्रेनिंग स्कूल से फेल पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अभी आदेश आया है, पोर्टल पर अपडेट अभी नहीं हुआ है होते ही फार्म 5 बी लेना पड़ेगा। कौशल कुमार सिंह, एआरटीओ प्रशासन, सोनभद्र

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जनपद में जागरूकता कार्यक्रम एवं औचक निरीक्षण अभियान संचालित

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र के निर्देशन में महिला

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमन, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्डलाइन एवं हंस फाउंडेशन के संयुक्त



एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा आज जनपद में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु सघन

तत्वावधान में महिला संकुल कार्यालय, बिल्ली-मारकुंडी, ओबरा (वि.खं.-चोपन) में किशोरियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।



जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1. चोपन क्षेत्र में जागरूकता एवं औचक निरीक्षण अभियान - महिला कल्याण विभाग की टीम द्वारा चोपन के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मंदिर परिसर एवं प्रमुख चौराहों पर औचक चेकिंग कर आमजन को जागरूक किया गया। इस दौरान बताया गया कि संकट में फंसी महिला या भटका हुआ बच्चा मिलने पर तत्काल आपातकालीन सेवा-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, महिला हेल्पलाइन-181, 1090, 102, 1076 पर सूचना दें। इन हेल्पलाइन के माध्यम से पीड़ित को सुरक्षित आवास, पुलिस सहायता, चिकित्सा, शैल्टर होम एवं विधिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। 2. महिला संकुल कार्यालय, बिल्ली-मारकुंडी में प्रशिक्षण कार्यक्रम -

कार्यक्रम में श्रीमती दीपिका सिंह, जेडए स्पोशलिस्ट श्रीमती साधना मिश्रा, परियोजना समन्वयक मुकेश सिंह, केस वर्कर सीमा शर्मा एवं प्रोजेक्ट मैनेजर सफरुद्दीन द्वारा किशोरियों को लैंगिक संवेदनशीलता, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (पीओएसएच) अधिनियम, आत्मरक्षा के उपाय, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गुड टच-बैड टच एवं लैंगिक उपीड़न की रोकथाम के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन सहित विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर एम्पलेंट वितरित किये गये। कार्यक्रम में बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।



NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE

(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)

सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी एण्ड इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी

फायर सेफ्टी पर जिसकी कमाण्ड, उसकी ही है ग्लोबल डिमाण्ड

कोर्स के बाद सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आदि विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल जाती है। रिलीफ एजेन्सी N.G.O., डिफेंस सर्विसेज फायर सर्विस आर्डिनेन्स फैक्ट्री, महानगर पालिका, नगर निगम, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, माइनिंग इण्डस्ट्रीज, पेट्रोलियम कम्पनी, फूड इण्डस्ट्रीज, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल मिल, टावर कम्पनी, इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी, कोयले की खदानों एवं जहाजों आदि क्षेत्रों में फायर सेफ्टी के जानकारों को बहुत अधिक मौका मिलता है

नोट: फायर सेफ्टी कोर्स करें और देश-विदेश, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पायें।

Visit us at www.nainiiti.com Call: 9415608710, 7459860480





श्री महन्त
अग्निशमन सुरक्षा अधिकारी नैनी, प्रयागराज

निजता को बनाए रखें और? गोपनीयता पर सजग रहें?

वैसे तो हर व्यक्ति रहस्यमयी है। वह क्या सोच रहा है और आपके साथ उसका क्या व्यवहार है, उग्र बीत जाती है और आप जान नहीं पाते हैं। गहन संबंधों में भी यह बात चलती है। दो शब्द हैं- निजता और गोपनीयता। सबसे निकट का संबंध है पति-पत्नी का। इन दोनों के बीच भी

यह स्थिति बनती है। इस रिश्ते में गोपनीयता होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन स्त्री और पुरुष की निजता बची रहनी चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य स्थान और ईंसान के मामले में निजता चाहता है।

समझदार जोड़े एक-दूसरे के प्रति गोपनीयता नहीं रखते।

200फीसदी पारदर्शिता का रिश्ता है यह। लेकिन एक-दूसरे की निजता का अत्यधिक मान भी करते हैं, क्योंकि निजता का संबंध कहीं ना कहीं आत्मसम्मान से भी है।

हम बुद्ध के उदाहरण से समझ सकते हैं। बुद्ध अत्यधिक रहस्यमयी थे, लेकिन डरावने

नहीं थे। वे उतने ही दयालु थे। हम जब भी सार्वजनिक जीवन में हों,

पारिवारिक जीवन में रहें, अपनी और दूसरों की निजता बनाए रखें और गोपनीयता कहां आवश्यक है और कहां नहीं, इसके प्रति भी जागरूक रहें। पं. विजयशंकर मेहता

दुनिया के शहर मिलकर भी क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पूरी दुनिया ही एक लड़ाई लड़ रही है। इस संघर्ष में लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन अंततः लोग इस दिशा में हुई प्रगति का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वे अपने दैनिक जीवन में क्या अनुभव करते हैं। और जलवायु कार्रवाई का प्रभाव दुनिया के शहरों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। शहरों में यह समझ अब बनने लगी है कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने और जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ाने वाले उपाय लोगों के दैनिक जीवन की भी बेहतर बनाते हैं। एनर्जी-इफिशिएंट घर बिजली के बिल को कम करते

विकल्प उपलब्ध कराता है। पेड़ और ग्रीन बेल्ट हवा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, इलाकों को ठंडा रखते हैं और शहरों को रहने के लिए अधिक सुखद बनाते हैं। लेकिन जलवायु कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही नहीं है। यह लोगों को गर्म होती पृथ्वी के पहले से स्पष्ट हो चुके प्रभावों से सुरक्षित रखने का भी प्रयास है। लू, बाढ़, सूखा और एक्स्ट्रीम-मौसम की घटनाएं लगातार अधिक तीव्र हो रही हैं। शहर और उनके निवासी इन चुनौतियों का सबसे पहले सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए एडाप्टेशन के उपायों को भी

सिस्टम्स बढ़ते तापमान के प्रति शहरों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसका सबसे अधिक लाभ बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील समूहों को मिलता है। आज दुनिया के कई बड़े शहरों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटा है, जबकि उनकी आबादी लगातार बढ़ती रही है। इसके अलावा, तमाम तरह के शहर मिलकर उस प्रगति को और तेज करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो उन्होंने अलग-अलग स्तर पर हासिल की है। पिछले एक दशक में ग्लोबल कोवेनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी (जीसीओएम) 150 देशों के 14,000 से अधिक शहरों और

जलवायु लक्ष्य अपनाए हैं और उन्हें अधिक तेजी से हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। फिर भी, यदि उन्हें अधिक सहयोग मिले तो वे और तेजी से तथा अधिक व्यापक स्तर पर काम कर सकते हैं।उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता और फंडिंग तक पहुंच वगैरे तत्काल आवश्यकता है।अनेक स्थानीय निकायों के पास अब भी इतने संसाधन नहीं हैं कि वे जलवायु परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन कर सकें।साझेदारी से इन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सिटी क्लाइमेट फाइनैन्स गैप फंड- जिसने जीसीओएम और विश्व बैंक का समर्थन प्राप्त है- पहले ही ऐसी परियोजनाएं विकसित करने में शहरों को सहायता दे रहा है, जो निवेश को आकर्षित कर सकें और आबादी को लाभ पहुंचा सकें। पिछले कुछ वर्षों में इसने 1,400 से अधिक शहरों को जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने में सहायता प्रदान की है।राष्ट्रीय सरकारें अब जलवायु परिवर्तन से निपटने में शहरों की क्षमता को तेजी से स्वीकार कर रही हैं। लेकिन इसे केवल शुरुआत माना जाना चाहिए। सबसे सफल जलवायु-नीतियां वही होती हैं, जिनका असर लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में देख और महसूस कर सकें, यानी स्वच्छ हवा, अधिक सुरक्षित सड़कें, बिजली का कम बिल, अधिक स्वस्थ घर और एक्स्ट्रीम-मौसम से बेहतर सुरक्षा। सबसे सफल जलवायु-नीतियां वही होती हैं, जिनका असर लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में देख और महसूस कर सकें, यानी स्वच्छ हवा, अधिक सुरक्षित सड़कें, बिजली का कम बिल, अधिक स्वस्थ घर और एक्स्ट्रीम-मौसम से बेहतर सुरक्षा। (प्रोजेक्ट सिंडिकेट,माइकल ब्लूमबर्ग)



हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आयातित-ईंधनों पर निर्भरता और तेल-गैस की कीमतों में उछाल से पैदा होने वाली मुश्किलों को कम करती हैं। बेहतर सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को आने-जाने के लिए अधिक किफायती और स्वस्थ

आगे बढ़ाना होगा। दुनिया भर में स्थानीय नेतृत्व स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और सार्वजनिक स्थलों को अत्यधिक मीमों तथा अन्य जलवायु जोखिमों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक बनाने के प्रयास कर रहा है। छायादार व्यवस्थाएं, ग्रीन रूफ और प्राकृतिक कूलिंग

स्थानीय सरकारों के गठबंधन के रूप में विकसित हुआ है, जो एक अरब से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भारत के भी 29 शहर शामिल हैं और सबसे नया सदस्य तिरुवनंतपुरम है। इसके अनेक सदस्य शहरों ने अपनी सरकारों की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी

बहुत सारे नए रोजगार भी क्रिएट करेगा एआई

तो क्या एआई हमारी नौकरियां खाने जा रहा है? अभी तो कोई नहीं जानता कि यह

पैदा होने वाले नए डेटा के प्रति एडाप्टिव भी हों। एआई को अपनाने में बाधा डालने वाला एक अन्य

प्रोडक्टिविटी में वृद्धि है (यह नहीं कि यह मानव-श्रम की तुलना में सस्ता पड़ता है), तो कंपनियों की



कितनी तेजी से होगा, कितना व्यापक होगा और इसका सबसे अधिक असर किन सेक्टर पर पड़ेगा। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग कंपनियां इस तकनीक को अपने कामकाज में कितनी तेजी से लागू करती हैं।अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के हालिया बिजनेस ट्रेंड्स एंड आउटलुक सर्वे के अनुसार, 20 से कम कर्मचारियों वाली केवल 20% कंपनियां ही वर्तमान में एआई का इस्तेमाल करती हैं, जबकि कम से कम 250 कर्मचारियों वाले 37फीसदी बिजनेसों में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बड़ी कंपनियां इस तकनीक का अधिक उपयोग कर रही हैं, लेकिन 37फीसदी का आंकड़ा भी कम ही है। फिलहाल, एआई को अपनाने की राह में एक बड़ी बाधा यह है कि पहले से ही असाधारण क्षमताओं वाली इस तकनीक को मौजूदा वर्कफ़ोर्स में इस तरह से कैसे समायोजित करें कि कंपनियां उसका पूरा लाभ उठा सकें। इसके लिए ऐसे मॉडल जरूरी हैं, जो न केवल मौजूदा डेटा पर प्रशिक्षित हों, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल से

फॉक्टर लागतों को लेकर अनिश्चितता है। कई बड़ी कंपनियां अभी भी पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं और नियुक्ति या छंटनी के फैसले ढाल रही हैं, क्योंकि वे स्थिति के और स्पष्ट होने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उन्हें इस तकनीक को अपनाने के लिए मजबूर करेगा ही। इसके बावजूद, रोजगार के लिहाज से भविष्य पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। अगर कंपनियां वही वस्तुएं बनाती और वही सेवाएं उपलब्ध कराती रहती हैं- जो वे अभी करती हैं- तो एआई को अपनाने का प्रभाव वही होगा, जो किसी भी नई तकनीक का होता है। हां, कुछ नौकरियां जरूर गैर-जरूरी हो जाएंगी, लेकिन कुछ अधिक प्रोडक्टिव और दिलचस्प भी होंगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि एआई ऊबाऊ और दोहराव वाले कामों को कम करेगा और उन कामों में मदद करेगा, जिन्हें ईंसान ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। साथ ही, नई नौकरियां भी पैदा होंगी- जैसे एआई इंजीनियरों की, जो इस तकनीक के इंप्लीमेंटेशन की निगरानी करेंगे। इसके अलावा, अगर एआई को अपनाने की वजह

कम लागत में अधिक उत्पादन करने की क्षमता उन्हें कीमतें घटाने और बिक्री बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। यह प्रसिद्ध जेवन्स-इफेक्ट है और इससे रोजगार भी बढ़ने चाहिए। आशावादी होने का एक और कारण यह है कि एआई नए बिजनेस खड़े करने में मदद कर सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फर्नीचर बनाने का कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन वह इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि इसके लिए उसे एक वेब-प्रोग्रामर और अकाउंटेंट की जरूरत है। अगर एआई ये दोनों भूमिकाएं निभा सके, तो शायद वह काफी कम लागत में एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय शुरू कर सकता है। महामारी के दौरान स्टार्टअप की संख्या पहले ही काफी बढ़ गई थी और हाल की तिमाहियों में इसमें और वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्री डेविड ऑटर बताते हैं कि एआई मध्यम कौशल वाले कामगारों को हाई-रिकल्स से लैस कर सकता है। इसका उदाहरण कोई नर्स प्रैक्टिशनर है, जो मेडिकल एआई की मदद से कहीं अधिक बीमारियों की पहचान और इलाज कर सकती है। दुनिया भर में चिकित्सा-सेवाओं की भारी मांग को

देखते हुए इस क्षेत्र में नए रोजगार पैदा करने की काफी गुंजाइश है। यह समझते हुए कि एआई के कारण नौकरियों के संकट का पहला दौर आखिरी नहीं होगा, कंपनियों को समय-समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और जहां तक संभव हो, उन्हें नौकरी पर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत होगी। सरकारें कर्मचारियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए टैक्स-क्रेडिट पर विचार कर सकती हैं, जिसमें कर्मचारी के काम पर बने रहने पर हर साल प्रशिक्षण की लागत का एक-तिहाई इस्तेमाल किया जा सके। अगर सरकार ऐसी नीति एआई अपनाने वाली कंपनियों पर लागू करना चाहती है, तो वो यह भी कर सकती है कि इस क्रेडिट का इस्तेमाल केवल टोकन टैक्स की भरपाई के लिए हो। हालांकि, कर्-प्रोत्साहनों से भी अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि कंपनियां स्वीकारें वे अपने कर्मचारियों को अनिश्चित भविष्य से निपटने में मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जैसे-जैसे रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ेगी, सबसे योग्य और प्रतिभाशाली लोग भी ऐसे एम्प्लॉयर के यहां नौकरी स्वीकार करने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, जो जब चाहे उन्हें नौकरी से निकाल सकता है। जो एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को सहयोग देने का वादा करेंगे, उन्हें अंततः एक अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है : उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो उनके पास चुनने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों का एक बड़ा पूल होगा। भविष्य निराशाजनक नहीं है-रोजगार के लिहाज से भविष्य पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। एआई को अपनाने का प्रभाव वही होगा, जो किसी भी नई तकनीक का होता है। कुछ नौकरियां जरूर गैर-जरूरी हो जाएंगी, लेकिन कुछ अधिक प्रोडक्टिव भी होंगी। नई नौकरियां भी पैदा होंगी- जैसे एआई इंजीनियरों की। रघुराम राजन

मुनाफा तय न करे कि कौन-सी जांच हो और कौन-सी दवा दें

भारत में निजी अस्पताल में दाखिले के साथ ही मरीज और परिवार के सामने दुविधाएं आ खड़ी होती हैं। अंतिम बिल कितना होगा, यह अकसर इलाज पूरा होने तक स्पष्ट नहीं होता। संसद में 7 अगस्त 2026 को पेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 176वीं रिपोर्ट ने इसी चिंता को सामने रखा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च 50,508 रुपये है, जबकि सरकारी अस्पताल में यह 6,631 रुपये है। प्रसव पर निजी संस्थान में औसत जेब खर्च 37,630 रुपये हैं, जबकि सरकारी संस्थान में केवल 2,299 रुपये। समिति ने कुल 368 सिफारिशें की हैं। इनमें इलाज शुरू होने से पहले संभावित खर्च बताना, मानकीकृत

ने इसी चिंता को सामने रखा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च 50,508 रुपये है, जबकि सरकारी अस्पताल में यह 6,631 रुपये है। प्रसव पर निजी संस्थान में औसत जेब खर्च 37,630 रुपये हैं, जबकि सरकारी संस्थान में केवल 2,299 रुपये। समिति ने कुल 368 सिफारिशें की हैं। इनमें इलाज शुरू होने से पहले संभावित खर्च बताना, मानकीकृत

खलनायक मानना सही नहीं होगा।समस्या पूंजी नहीं, यह है कि पूंजी से मिलने वाले लाभ की अपेक्षा कहीं चिकित्सा निर्णयों को प्रभावित न करने लगे। स्वास्थ्य-सेवा सामान्य बाजार नहीं है। बीमार व्यक्ति कार या मोबाइल खरीदने वाले ग्राहक की तरह अलग-अलग दुकानों में कीमतों की तुलना नहीं कर सकता। अस्पताल ही काफी हद तक तय करता है कि मरीज का क्या इलाज करना

शुरू होती है। अधिक जांचें ऐसी छोटी असामान्यताएं पकड़ सकती हैं जिससे मरीज को जीवनभर कोई नुकसान नहीं होता। फिर उनके पीछे नई जांचें होती हैं। सामान्य सीमा के आसपास की स्थिति बीमारी घोषित हो सकती है। जिसे घर पर दवाओं व निगरानी से संभाला जा सकता था, वह अस्पताल में भर्ती हो सकता है। जहां इंतजार और निगरानी उचित थी, वहां प्रक्रिया की सलाह दी जा सकती है।



सम्पत्ति वाले दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। डेटा, तेल और एआई- इन तीन बड़ी बातों से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की बादशाहत को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 5 सालों में 500 अरब डॉलर यानी 47 लाख करोड़ रुपए की अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए भारत पर दबाव बढ़ रहा है। उसी कड़ी में भारत में डेटा सेंटरों की स्थापना हो रही है, क्योंकि अमेरिकी डेटा सेंटरों के लिए मशीनों और सेवाओं का भारत में आयात होगा। इस परिदृश्य के पांच पहलुओं को समझना जरूरी है : 1. अमेरिकी एआई कंपनियों को सफल होने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर की जरूरत है। हमारे आम बजट में सिर्फ 1 साल के लिए टैक्स के नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका के दबाव में इस साल के बजट

स्थापित करने का लक्ष्य है। स्वदेशी कंपनियों को टैक्स छूट नहीं मिलना संविधान की समानता के उल्लंघन के साथ सार्वभौमिकता का भी हनन है। 2. दुनिया के कुल डेटा का लगभग 25फीसदी भारत से जनरेट हो रहा है। भारत में डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं होने से अमेरिका की टेक कंपनियां और मालिक मालामाल हो रहे हैं। पिछले साल यूपीआई से 314 लाख करोड़ के लेंनदेन हुए, जो ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट का 49फीसदी है। रिजर्व बैंक ने 2018 में डेटा को भारत में सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाए थे, जिन्हें विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं किया जा रहा है। 3. केंद्र सरकार ने पिछले साल कहा था कि विदेशी कंपनियों को भारत में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करने के बाद ही टैक्स में छूट मिलेगी। अब उन्हें भारत

हैं। खरबों डॉलर के निवेश वाले इन डेटा सेंटरों से औद्योगिक क्रांति नहीं होने से दीर्घकालिक रोजगारों का सृजन भी नहीं होगा। 4. डेटा सेंटरों को चौबीसों घंटे बिजली चाहिए या डीजल वाले जनरेटर सेट के बैंकअप की जरूरत होगी। चार सालों में डेटा सेंटरों में बिजली की खपत 6 गुना बढ़ जाएगी। इनकी सहूलियत के लिए भारत में परमाणु बिजली का कानून नया बनाया गया है। इनसे चेन्नॉबिल जैसे हादसे होने का खतरा बढ़ गया है। राज्यों की बिजली कंपनियों सात लाख करोड़ के कर्ज से दबी हैं। डेटा सेंटरों की वजह में ऊर्जा के साथ विदेशी मुद्रा का संकट गहरा सकता है। 5. गर्मी के उत्सर्जन और रैडिएशन की वजह से अमेरिका में डेटा सेंटर बंद करने का आंदोलन चल रहा है। दुनिया के सबसे गर्म 100 शहरों

प्रस्त हैं। खरबों गैलन पानी निगलने वाले डेटा सेंटरों के वजह से भूगर्भजल के साथ पेयजल का संकट गहरा सकता है। अंतरिक्ष और समुद्र में डेटा सेंटर के खाब बेचकर मस्क टेक-कुबेर बन गए हैं। गरीबी, एकाधिकार, बेरोजगारी, जलवायु जोखिम और साम्राज्यवाद बढ़ाने वाले विदेशी डेटा सेंटरों की टैक्स छूट खत्म हो। संविधान के अनुसार डेटा सेंटरों में पर्यावरण संरक्षण और श्रम कानूनों को लागू करने की जरूरत है। हमारे आम बजट में सिर्फ 1 साल के लिए टैक्स के नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका के दबाव से इस साल के बजट में विदेशी क्लाउड कंपनियों को साल 2047 तक इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। इसका क्या कारण है? (ये लेखक के अपने विचार हैं,विराग गुप्ता)

पैकेज दरें तय करना और अस्पतालों के शुल्क में पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। एक सुझाव यह भी है कि महानगरों में निजी अस्पतालों के सामान्य कमरों का शुल्क आसपास के तीन सितारा होटलों के औसत किराये से अधिक न हो। बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों से अपेक्षा की गई है कि मेडिकल ट्रिज्म, विदेशी मरीजों और संपन्न वर्ग से होने वाली आय का कुछ लाभ गरीबों तक पहुंचे। लेकिन भारत को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निजी और विदेशी पूंजी की जरूरत है। अस्पताल बनाना महंगा है। जमीन, आधुनिक उपकरण, आईसीयू, प्रयोगशालाएं, डिजिटल तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारी- सबके लिए बड़ा निवेश चाहिए। सरकारी अस्पताल अभी अकेले देश की सारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते।

इसलिए निजी अस्पतालों और विदेशी निवेश को खलनायक मानना सही नहीं होगा। भारत में निजी अस्पतालों में दाखिले के साथ ही मरीज और परिवार के सामने दुविधाएं आ खड़ी होती हैं। अंतिम बिल कितना होगा, यह अकसर इलाज पूरा होने तक स्पष्ट नहीं होता। संसद में 7 अगस्त 2026 को पेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 176वीं रिपोर्ट ने इसी चिंता को सामने रखा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च 50,508 रुपये है, जबकि सरकारी अस्पताल में यह 6,631 रुपये है। प्रसव पर निजी संस्थान में औसत जेब खर्च 37,630 रुपये हैं, जबकि सरकारी संस्थान में केवल 2,299 रुपये। समिति ने कुल 368 सिफारिशें की हैं। इनमें इलाज शुरू होने से पहले संभावित खर्च बताना, मानकीकृत

है।एमआरआई जरूरी है या नहीं, भर्ती दो दिन और चले या नहीं, एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है या दवाओं से इलाज हो सकता है- इन फैसलों में डॉक्टर और अस्पताल के पास मरीज से कहीं अधिक जानकारी होती है।

यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी इन्फॉर्मेशन एसीमेट्री या ज्ञान-असमानता है, जिसके बारे में अर्थशास्त्री लम्बे समय से बताते रहे हैं।कॉर्पोरेट अस्पतालों में महंगी तकनीक, नामी विशेषज्ञ और बेहतर सुविधाएं गुणवत्ता बढ़ा सकती हैं। लेकिन इनकी लागत भी वसूलनी होती है। संस्थानों पर लगातार बेड़ भरने, प्रति मरीज आय बढ़ाने या अधिक जांचें कराने का दबाव होता है। अधिकांश डॉक्टर मरीज का हित ही चाहते हैं, लेकिन संस्थागत प्रोत्साहन चिकित्सकीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

यहाँ से 'ओवर- मेडिकलाइजेशन' की समस्या

सी जे रियन ऑपरेशन, एंजियोफास्टी, आईसीयू भर्ती, डायग्नोस्टिक पैकेज और लंबी दवा-सुचियों पर इसलिए केवल व्यक्तिगत चिकित्सकीय फैसलों के रूप में नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य-तंत्र के प्रोत्साहनों के संदर्भ में भी विचार होना चाहिए। हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश चाहिए। जहां मुनाफ़े की अपेक्षा यह तय करने लगे कि कौन-सी जांच होगी, कौन-सी दवा लिखी जाएगी और कौन-सी प्रक्रिया की जाएगी।स्वास्थ्य-व्यवस्था की सफलता अस्पतालों में आए निवेश या मेडिकल ट्रिज्म की वृद्धि से नहीं मापी जानी चाहिए। असली कसौटी यह है कि मरीज अस्पताल में इस भरोसे से प्रवेश कर सके कि उसे उतना ही इलाज मिलेगा, जितना जरूरी है- न उससे कम, न अधिका। (ये लेखक के अपने विचार हैं) डॉ. चन्द्रकान्त लहाय्या

बांग्लादेश बोला- भारत से गंगा जल समझौते में गारंटी मांगेंगे, जरूरत पड़ी तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाएंगे, 1996 का समझौता दिसंबर में खत्म होगा

दिल्ली/ढाका। इस दौरा गंगा नदी में पानी अपेक्षाकृत कम रहता है। बांग्लादेश को गारंटी क्यों चाहिए-बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि में पानी बांटने का फॉर्मूला तो है, लेकिन तय

की मांग कर रहा है। भारत ने सत्तर के दशक में पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बनाया था। इसका मकसद गंगा के पानी के एक हिस्से को हुगली नदी की तरफ भेजना था, ताकि हुगली

1977 में पहली बार दोनों देशों में समझौता-फरक्का को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवाद चलता रहा। भारत का कहना था कि फरक्का से पानी मोड़ना उसके लिए जरूरी

कि दोनों देश तुरंत बाबाचीत करके आपात स्थिति में पानी के बंटवारे को समझ में बढावा करिए। भारत दिवसगत यहाँ से शुरू हुई कि 1996 के समझौते में 'पानी कम पढ़ने पर क्या करना है' तो लिखा गया था लेकिन वह साफ नही लिखा गया कि उस स्थिति में बांग्लादेश को कम से कम किताप पानी मिलना ही चाहिए। गया जल समझौते को लेकर भारत का क्या रुख है-भारत का कहना है कि 1996 के बड़े गंगा जल समझौते ने नवीनीकरण पर बांग्लादेश के साथ औपचारिक बाबाचीत अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि, भारत ने अपनी स्थिति तयार करने की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल और अन्य संबंधित पक्षों की चिंताओं को शामिल किया है। भारत सरकार का कहना है कि नया समझौता तैयार करने समथ- नाल जल प्रवाह के आकड़े देखे जाएं। जलवायु परिवर्तन का असर देखा

सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से केजरीवाल-सत्येंद्र जैन को लेटर लिखा, 3 और घोटाले उजागर करने की धमकी दी, आप को घोटालों की ऑलवेज पार्टी बताया

नयी दिल्ली। सुवेण्श
चंद्रशेखर ने जेल से आम आदमी

लॉन्ड्रिंग मामलों में तिहाड़ जेल में बंद हैं। (अरविंद केजरीवाल)

तीन अन्य विभागों में तीन और घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर

मांगे थे, जो उसने दिए। 7
अक्टूबर, 2022: सुवेश ने



किए जाऐंगे।
 आम आदमी
 पार्टी का अब
 मतलब है
 एन्री टाइम,
 ऑलवेज पार्टी
 ऑफ स्क्विम
 है। पंजाब को
 फिर से
 बड़े वायू प्लांट
 बनाने की
 बात भूल
 जाइए। दिल्ली
 में जो हुआ,
 पंजाब में
 आपकी अलइ
 और आपकी
 घोटाले वाली
 पार्टी लेस
 रिखला पाए।
 इससे भी
 ज्यादा गुस्सा
 लिखेगा। आप

तत्कालीन उपराज्यपाल वीरेंद्र सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आरोप सरकार को तत्कालीन मंत्री सायद जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश ने दावा किया था कि जेल में सुखा और सुविधाएं देने के नाम पर जैन ने उससे 10 करोड़ रुपए वसूलें थे। उसके मुताबिक, वह रकम जैन के सहयोगी के जरिए कोलकाता में ही गई थी। दिल्ली पुलिस ने 2017 में सुकेश को गिरफ्तार किया था-सुकेश पर कई मामलों में अपराधी माना गया। चाल रहे हैं। 2017 में एआईडी डीएमके के 'दो पत्नी' चुनाव चिह्न मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2020 में उसे तिहाड़ से रोहिणी जेल ट्रांसफर किया गया था। 2021 में सुकेश पर आरोप लगा कि उसने रैनबैक्स की पूर्व प्रमोटर शिविंद सिंह की पुत्री अमिंद सिंह से करीब 10 करोड़ रुपए वसूलें थे।

मात्रा में पानी मिलने की कानूनी गारंटी नहीं है। इसलिए वह नई संधि में 'गारंटी कलॉज' जोड़ने की मांग कर रहा है। गारंटी कलॉज ऐसा नियम है, जो सुनिश्चित करता है कि नदी के निचले हिस्से में बसे देश को भी जरूरत का पानी मिलता रहे। इसका मतलब है कि अगर नदी में पानी कम भी हो जाए, तब भी उसे एक तय मात्रा में पानी दिया जाएगा। बांग्लादेश चाहता है कि अगर किसी साल पानी कम हो या किसी कारण से समझौते का पालन न हो, तो उसका समानान कैसे होगा और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी समझौते में साफ लिखा जाए। बांग्लादेश का कहना है कि 1977 के गंगा जल समझौते में यह व्यवस्था थी, लेकिन 1996 की संधि में इसे शामिल नहीं किया गया। इसलिए वह नई संधि में इस प्रावधान को जोड़ने

मे पानी का बहाव बढ़े और
कोलकाता बंदरगाह में जमा होने
वाली ग़ाद को कम करने में मदद
मिले। ग़ाद कम करना इसलिए
ज़रूरी था क्योंकि मिट्टी और
कीचड़ जमा होने के कारण
बंदरगाह और हुगली नदी की
गहराई लगातार घट रही थी।
इससे कोलकाता बंदरगाह के ठप
होने का खतरा था। समस्या यह
थी कि गंगा भारत से निकलकर
बांग्लादेश में भी जाती है।
इसलिए भारत ने जी पानी का
कुछ हिस्सा अपनी तरफ मोड़
दिया तो इससे वहां जाने वाले
पानी की मात्रा कम होने लगी।
इससे बांग्लादेश में कई तरह की
समस्याएं बताई गईं- सिंचाई के
लिए पानी कम पड़ना, खेती पर
प्रभावित होना, मछलियां और
जलीय जीवन पर असर, नदी में
ग़ाद बढ़ना, खारे पानी का ऊपर
की ओर आना नदी और
असपास के पर्यावरण पर असर

हे, जबकि बांग्लादेश लगातार अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहा। अखिरकार दोनों देशों ने पानी को लेकर अलग-अलग समझौते किए। 1977 का समझौता हुआ, जिसमें पानी के बंटवारे के साथ एक गरीबी क्लॉज भी था। पानी कुछ परिस्थितियों में बांग्लादेश को न्यूनतम मात्रा में पानी मिलने की गारंटी दी गई थी। 1977 का समझौता 1982 व 5 साल के लिए था और 1985 में खत्म हो गया। इसके बाद 1982 और 1985 के समझौता ज्ञापनों में भी गरीबी क्लॉज नहीं था। बाद में 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल के लिए गंगा जल समझौता हुआ। इसमें सूखे के मौसम में पानी के पानी के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया। इसमें पानी देने की न्यूनतम मात्रा की गारंटी नहीं दी गई। इसके बजाय कहा गया

जुहरतो को ध्यान में रखा जाए। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे पश्चिम दिशा में सहाय रिफ्ट्स संविगत राज्यों से सलाह ली जाए। समझौते को ठेकर प. बंगाल और बिहार का रुख-गंगा का फरक्का बाला हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, इसलिए समझौते का सीधा पश्चिम राज्य पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल का कहना है कि भारत, बांग्लादेश को जतना ही पानी दे जिससे राज्य में उपलब्ध पानी पर असर न पड़े। बिहार का कहना है कि फरक्का की वजह से गंगा में गाद जमा हो रही है, जिससे नदी की गहराई कम हो रही है और बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर फरक्का को हटाने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि फरक्का के फायदे से ज्यादा नुकसान है।

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नयन लेटर लिखा है। लेटर में उसने पार्टी से जुड़े तीन और घोटाले उजागर करने की धमकी दी है। चंद्रशेखर ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति और जल बोर्ड को लेकर उसके पिछले खूबसे सही साबित हुए हैं। यह लेटर गुरुवार को सामने आया। उसने आम आदमी पार्टी को घोटालों की ओलवेज पार्टी बताते हुए पंजाब को लेकर भी चेतावनी दी है। सुकेखा घोखाधड़ी और मन

को लिखी लेंटर का हिस्सा।
केजरीवाल जी, देश के युवाओं को
आँजैन जी को भड़काने के लिए
जिन प्रॉक्सि लोगों का आपका
इस्तेमाल कर रहे हैं, वह कामों में
नहीं करेगा। आपके प्रॉक्सि लोगों का
भाभी खुलासा होगा। यह मेरा
बिफोर नीथिंग एल्स काम होगा।
सुलेश चंद्गखर, आपत्ते
प्रोत्पादक को उजागर करने की
दिशा में यह एक और कदम है।
2021-22 के मेरे खुलासे सही-सही
साबित हुए हैं। शराब नीति/निर्णय
मामले के बाद अब जिन बोर्ड का
मामला सामने आया है। आपके

लोग ध्रुम में हो सकते हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं जल्द ही आपको चौकाऊंगा। केजरीवाल जी और सत्येंद्र जी, जेल से आपके लिए 2.0 बधाई। अब यहाँ मैं आने वाला हूँ। सुकेश के पिछले 2 डेटर में आप पर लगाए आरोप- 4 नवंबर, 2022: सुकेश ने मीडिया के नाम तीन पत्रों की चिट्ठी लिखी थी। इसमें उसने दावा किया था कि अगर वह ठग हैं तो केजरीवाल 'महाठग' हैं। सुकेश ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने राजस्थान सीट के लिए के बदले उससे 50 करोड़ रुपये

कराई रुपए की ठगी की थी। इसके बाद उस पर थोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया गया। फिर तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस मामले में ईडी की जांच में सामने आया था कि सुकेश ने ठगी के इन पैसों से एक्ट्रेस जैकलीन को कराई रुपए के कीमती गिफ्ट्स दिए थे। इसमें लज्जरी बैग, हीरो की ज्वेलरी, महंगे घड़े और बिलियार्ड शामिल थी। इस वजह से 'उ' ने जैकलीन को भी इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया था।

पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ में हुआ निधन, सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद काट रहे थे

नयी दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के

में गुरुद्वारे को जलाने का मामला था। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया, जबकि दूसरे आरोपियों को दोषी ठहराया गया। 17 दिसंबर

शाह बोले- कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम न गाना देशविरोधी, उन्होंने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तृष्ठीकरण किया और विभाजन की शुरुवात की

नयी दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न

वंदे मातरम विवाद पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक

इसकी टाइमिंग 3 मिनट 10 सेकेंड बताई गई है। साथ ही राष्ट्रगीत के गायन/वादन के

संस्करण को गाने का निर्देश है। हालांकि, दोनों नोटिफिकेशन में छंद न गाने पर कार्रवाई करने की



मुताबिक उन्हें मृत अवस्था में सफ़दराथंग अस्पताल में लाया गया था। सज्जन कुमार दिसंबर 2018 ने जेल में बंद थे। 7 साल 8 महीने जेल में रहने के बाद आज उनका निधन हो गया। उन्हें 1984 सिख विरोधी दंगों के दो मामलों में प्रचुरद्ध की सजा मिली थी, जबकि दंगों से ही जुड़े दो केस में बरी हो गए थे। 1984 दंगे- सज्जन पर सिखों की हत्या का आरोप-31 अक्टूबर 1984: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 नवंबर से दिल्ली समेत कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। दिल्ली में करीब 2700 लोग देशभर में लगभग 3500 लोगों की मौत हुई। मई 2000: इसकी नानावटी कमीशन बना जाइती सिफाफिराज पर 24 अक्टूबर 2005 को ढँ ने केस दायर किया। तब सज्जन कुमार सांसद थे। उन्हें दो भड़काने और सिखों की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया। 2010-2013: दायल कोर्ट ने सज्जन कुमार समेत कई आरोपियों को

2018 के दिल्ली हाईकोर्ट ने दाय कोर्ट का फैसला पलट दिया और सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया, उन्हें उम्मीदों की सजा दी गई। 31 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार ने कड़कड़मा कोर्ट में सर्रेज किया और उन्हें मंडोली रिहा भेजा गया। यही वह कैस है जिसके कारण वह दिक्कत 2018 से जेल में रहे।

2. सुलतानपुरी केस- 20 सितंबर 2023 को बरी: सुलतानपुरी इलाके में दंगो और हिंसा के जुड़ाव केस भी 1984 के दंगों का महत्वपूर्ण मामला था। 20 सितंबर 2023 को राउज पेन्शनरी कोर्ट ने सज्जन कुमार और दूसरे आरोपियों को बरी कर दिया।

3. सरस्वती विहार केस- दूसरी बार उम्मीद: 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में तजपत सिंह और अन्य के बेटे जयदीप सिंह की हिंसा के घरे केस लंबे समय तक बंद था। 2015 में 1984 दंगों के मामलों की दोबारा जांच के लिए बनाए गए नए पुराने मामलों की जांच के

गाने का फौसला हैरान करने वाला और देशविरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फौसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उन्होंने कहा- कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रपति के दो दुल्हे कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फौसले से दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के सांसद केली वेणुगुणा पाल के कहा- वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी। उनके लिए यह राजनीतिक मुद्दा है। दरअसल, कांग्रेस वकिंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती दो पैरा गाएगी। यह फौसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद आया। शाह ने कहा- कांग्रेस देश का कानून नहीं मान रही- अमित शाह ने कहा, कांग्रेस का सिर्फ दो पैरा वंदे मातरम गाने का फौसला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने का फौसला किया था। आज कांग्रेस उसी पुराने फौसले को फिर लागू कर रही है। देश की जनता को कांग्रेस के इस फौसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बीजेपी इसका जनता के बीच इस संसद और विधानसभा में भी जोरदार विरोध करेगी। नितिन गदीन बोले- कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बना गई-

को राजनीति के लिए राष्ट्रीय गीत को अपमान किया है। कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। वह फैसला वंदे मातरम को अपने मन में रखकर बलिदान देने वाले शहीदों का अपमान है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम के बाद विवाद हुआ। वंदे मातरम को लेबर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में सत्रतागत दिवस समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने इसका वीडियो भी एक्स पर शेयर किया और दावा किया कि राहुल गांधी भी पूरे गायन के दौरान परेशान दिखे। कांग्रेस ने कहा था- खण्डों के लिए कुर्सी मांग रही थी सोनिया-भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस महासचिव जयप्रकाश मोहन ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाय गया था और इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। उनके मुताबिक, सोनिया गांधी का इशारा गीत रोकने के लिए नहीं था। वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं क्योंकि वे लंबे समय से छुट्टी थे। वंदे मातरम पर नोटिफिकेशन और कानून क्या कहते हैं? 1. नोटिफिकेशन-1: 31 जनवरी 2026- गृह मंत्रालय ने 'ऑर्डर रिलेगिड टू दे नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया' जारी किया। इसमें 'वंदे मातरम' के 36 पंक्तियों को आधिकारिक संस्करण बताया गया है। आदेश के मुताबिक जब राष्ट्रगीत गाय जाये, तो अधिकारिक यानी पूरा संस्करण गाया जाना चाहिए।

दौरान समान, शिष्टाचार बनाए रखने, साथ ही इसे सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़े होने का निर्देश है। 2. कानून: जुलाई-अगस्त 2026-प्रवेशन ऑफ़ ईसटर्न ट्रेडेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल जुलाई 2026 में लाया गया। राज्यसभा ने इसे 29 जुलाई और लोकसभा ने 30 जुलाई 2026 को पास किया। 11 अगस्त को कानून बना। इसका मकसद 'वंदे मातरम' को 1971 के कानून के तहत कानूनी सुरक्षा देना है। संशोधन में कहा गया है कि जो गीत गीत चित्र जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकता है या उसके गायन में शामिल सभा में रुकावट डालता है, उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 3. नोटिफिकेशन-2: 9 जुलाई 2026-गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान से जुआदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। आदेश में कहा गया कि दोनों के सही पाठ, उच्चारण और तय प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। यदि राष्ट्रीय और राष्ट्रगान दोनों गाय या बजाए जाएं, तो पहले राष्ट्रगीत और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। आदेश में इन निर्देशों के उल्लंघन के लिए कोई अलग सजा नहीं बताई गई है, बल्कि संबंधित संस्थानों और संगठनों को इन्हें सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इन तीनों से क्या निष्कर्ष? नोटिफिकेशन के मुताबिक वंदे मातरम के पुरे 6 छंद ही इसका आधिकारिक स्वरूप है। जब राष्ट्रगीत गाय जाता है, तो इसी पुरे

1937 को समझाया कि पहले 2 थेंदों में
में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी
समुदाय की धार्मिक भावना के
खिलाफ हो।
लैकिन बाद के हिस्सों में
धार्मिक प्रतिक्रिया, कल्पना और रूपाकार
आते हैं। इसलिए पूरे देश के लिए
ऐसा हिस्सा चुना गया, जिसे सभी
समुदाय आसानी से स्वीकार कर
सकें। 6 अप्रैल 1938 को जिम्मा को
लिखे पत्र में नेहरू ने यही बात
दोबारा कही। ब्रिक्म चटर्जी ने 1875
में लिखा था, आनंदमठ में छा था-
भारत के राष्ट्रीय वंदे मातरम को
ब्रिक्म चटर्जी ने 7 नवंबर 1875
को अक्षय नारायण पर लिखा था। यह
1882 में पहली बार उनकी पत्रिका
ब्रान्दार्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ
के हिस्से के रूप में छा था।
1896 में भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ
टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया।
यह पहला मौका था जब यह गीत
सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर
गाया गया। सभी में मौजूद हजारों
लोगों की आंखें नम हो गईं। वंदे
मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है-
जिसका मतलब है- हे मां, मैं तुम्हें
नमन करता हूँ।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
मातरम भारत की औपनिवेशिक
शासन से संयुक्त करारों के लिए संघर्ष
कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों का नारा
बन गया था। गणतंत्र दिवस पर
वंदे मातरम की झण्डा निकली
थी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य
पेड़ में इस साल 77वें गणतंत्र दिवस
में मुख्य पेड़ की थीम वंदे मातरम
रखी गई थी।
पेड़ में संस्कृति मंत्रालय ने
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने
का जश्न मनाने वाली झंडी निकाली
थी। इस झंडी को मंत्रालय और
विभागों की कंटेनरों में बेस्ट झंडी
का अवॉर्ड मिला।

कुमार को बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की। 17 दिसंबर 2018: दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार का उम्रकैद की सजा सुनाई। 2005: दौंगे के 21 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगते हुए कहा था कि इस घटना से उनका सिर शर्म से झुक जाता है। 4 मामले- 2 में बरी, 2 में उम्रकैद-सज्जन कुमार 20 अगस्त 2026, याने उनकी मौत होने से पहले तक राजनगर और सरस्वती विहार से जुड़े 2 मामलों में दोषी थे, उन्हें उम्रकैद मिली थी, बाकी दूसरे 2 मामलों में बरी/डिस्चार्ज कर दिया गया था। पहिले कौन सा मामला क्या था- 1. राज नगर केस- पहिले बरी, फिर उम्रकैद: दिल्ली कैद के राज नगर/पालम कॉलोनी में 1 नवंबर 1984 को एक ही सिख परिवार के 5 सदस्यों की हत्या और राज नगर

को राज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। 25 फरवरी 2025 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उम्र, स्वास्थ्य और जेल में आचरण को देखते हुए मृत्युदण्ड नगिर्द किया। यह उनका दूसरा कनिष्कवर्ष था। 4. जनकपुर विकासपुरी केस - 22 जनवरी 2026 को बरी: यह अभी हाल का और का गैरकानूनी मामला है। इस केस में दो एफआईआर शामिल थीं। पहली एफआईआर में आरोपी था कि 1 नवंबर 1984 को जनकपुर इलाके में हुई हिंसा में सोहन सिंह और उनके दादादा अवतार सिंह की हत्या और लूटपाट/आगजनी हुई। दूसरी एफआईआर 2 नवंबर 1984 को गुरचरण सिंह को जिंदा जाले और उसे जुड़ी हिंसा का मामला था। दोनों मामलों को बाद में एक चार्जशीट में रखा गया था। जनवरी 2026 को राज एवेन्यू कोर्ट ने सजेन कुमार को बरी कर दिया।

छात्र संगठनों के बीच जनरल मीटिंग में हिंसक झड़प हो गई। कौंसे छात्र दण्डवत् हुए और कौंसिलरों में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। छात्र संगठनों ने मुताबिक, विवाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल मीटिंग को लेकर शुरू हुआ। बैठक में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने के बाद मारपीट हो गई। एबीवीपी ने लेफ्ट संगठनों पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं, वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर बाहरी लोगों को बुलाने और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इनमें एकदम से ग्यूप नारे लगाते हुए बंद कमरों और दूसरी जगहों में घुसने की कोशिश करता दिख रहा है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाशाला गंभीर आरोप-एबीवीपी ने आरोप लगाया कि वामपंथी छात्र संगठनों की आम बैठक की आड़ में

एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, वामपंथी छात्र संगठनों के एबीवीपी पर बाहरी लोगों को कैप्स में लाने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। फिलॉसफी के छात्र और रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट के सदस्य अभिनव दास ने दावा किया कि एबीवीपी समेत कई बाहरी लोग बैठक में पहुंचे थे। एबीवीपी का पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन, आज विरोध का ऐलान एबीवीपी के केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य शुभ्रत अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एबीवीपी से जुड़े कुछ सदस्य जादपुर पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

एबीवीपी ने बुधवार रात हुई घटना के विरोध में गुरुवार सुबह 11 बजे प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पुलिस की मौजूदगी के बीच यूनिवर्सिटी में तनाव को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

लखनऊ- यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन की हत्या कर फिर बहन को मारकर खुदकुशी की

लखनऊ में एसबीआई के फील्ड ऑफिसर ने बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी और अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर

भाग गया। इसके बाद 12:30 बजे वह सीधे 2 किमी दूर अपने घर पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मानस पसीने से भीगा हुआ था।



खुद भी गोली मारकर जान दे दी। पूरे वारदात को उसने फ्लॉग करके अंजाम दिया। गुरुवार दोपहर करीब 12:05 बजे मानस कार से आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा। फोन करके पत्नी दिया मिश्रा को ऑफिस से बाहर बुलाया। थोड़ी देर उनसे बातचीत की, फिर गोली मारकर

अदर जान के बाद उनसे सबसे पहले कम्परे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर टीवी पर तेज आवाज में नुसुमान चालीसा चला दी। इसके बाद मांसन ने बहन शीबा की गोली मारकर हत्या कर दी। शीबा मानसिक बीमार थी। उसका इलाज चल रहा था। मांसन को डर था कि उसके मरने के बाद बहन की देखभाल कौन करेगा? इसके बाद मांसन ने खुद को भी गोली मार ली। दो गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी भायाकर पहुँचे और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर भाई-बहन की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। वारदात गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अफसर मौके पर पहुँचे। फॉरेंसिक टीम ने जांच की। पुलिस कम्पिन्सट्रिग ने गांव की भी सड़क कम्पिन्सट्रिग ने गांव की भी सड़क

